

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 16, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), जनसंपर्क विभाग, आयुक्त, जनसंपर्क तथा मु.का.अ., छ.ग. संवाद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से सौंपता है.

2. श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005), विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), जनसंपर्क विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, जनसंपर्क एवं मु.का.अ., छ.ग. संवाद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

सहकारिता विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2018

क्रमांक/एफ 15-42/15-2/2018.—छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 10841/4065/XXI-B/2018 दिनांक 02-11-2018 द्वारा श्री जगदम्बा राय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी की सेवाएं सहकारिता विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री जगदम्बा राय को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, बिलासपुर में प्रतिनियुक्ति पर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-10/2018/11/6.—विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06-10-2018 की अनुशंसा के आधार पर, राज्य शासन एतद् द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार नारनवरे, निरीक्षक, पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें, दुर्ग को सहायक पंजीयक, पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें के पद पर पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स के लेवल-12 (वेतनबैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन 5400/-) पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, वर्तमान पदस्थापना स्थल यथावत रखते हुए, पदोन्नत करता है।

2. उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी में से यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी की वरिष्ठता अथवा न्यायालय प्रकरण में पदोन्नति की पात्रता हेतु भविष्य में कोई पदोन्नति की पात्रता संबंधी निर्णय/आदेश होता है तो संबंधित अधिकारी को पद अभाव के कारण पूर्व पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।
3. उक्त पदोन्नति हेतु कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर छ.ग. के पत्र क्रमांक 247/स्था/2018/6067, दिनांक 06-11-2018 द्वारा पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना स्थान में परिवर्तन नहीं होने तथा निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित नहीं होने की शर्त पर सहमति प्रदान की गई है।
4. पदोन्नत अधिकारी की पदस्थापना पृथक से आदेश जारी कर की जाएगी।
5. प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अधीन निर्धारित आरक्षण (रोस्टर) का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 1-09/2018/10-भा.व.से.—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2018 द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2018 से “छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण” का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा अब छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में कार्य करने वाला भारतीय वन सेवा का अधिकारी “जो मुख्य वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी का ना हो” को दिनांक 30-09-2018 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण नामित किया जायेगा।

श्री व्ही. श्रीनिवास राव, भा.व.से. (1990) को शासनादेश क्रमांक एफ 1-02/2018/10-भा.व.से. दिनांक 27-08-2018 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया था। राज्य शासन एतद्वारा श्री व्ही. श्रीनिवास राव, भा.प्र.से. (1990) को दिनांक 30-09-2018 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नामित करता है। उनके कर्तव्य एवं दायित्व यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार चौधरी, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 10-4/2016/16.—राज्य शासन एतद्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबंधों के अनुसरण में निम्न अनुसूची के “अगरबत्ती उद्योग में नियोजन” में पुनरीक्षण का प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-10-4/2016/16, दिनांक 02-02-2018 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 09-03-2018 में प्रकाशित किया था, जिसके संबंध में निर्धारित समयवाधि में कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 तथा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्वद के परामर्श अनुरूप “अगरबत्ती उद्योग में नियोजन” के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार पर जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 तक अवधि में हुई औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक योग 1285 के आधार पर नियत मूल वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को विलय करने के उपरांत प्राप्त न्यूनतम वेतन की दरों में उक्त प्राप्त न्यूनतम वेतन में 50% की वृद्धि करते हुए एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के वर्गों के लिये, कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कालम (4) में दर्शाये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें पुनरीक्षित करता है तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार पुनरीक्षित की गई न्यूनतम वेतन की दरें इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी :—

अनुसूची

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु. 26.96 पैसे	(मूल्य सूचकांक के आधार पर) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)

(1)	(2)	(3)	(4)
	साधारण सुगंधित (सेंटेंड)	रु. 27.66 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)

आ. निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना.

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 22.05 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 22.76 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 22.76 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 28.89 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 38.79 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 44.57 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 45.87 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 56.41 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)

सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 22.76 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 28.37 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 36.30 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 37.05 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 39.15 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 45.87 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 54.99 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु. 57.81 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)

(1)	(2)	(3)	(4)
ई.	निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना.		

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा	रु. 18.29	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु)
2.	12 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा	रु. 18.96	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु)
3.	23 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा	रु. 22.73	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)
4.	50 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा	रु. 23.46	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)
5.	100 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा	रु. 28.37	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)
6.	200 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा	रु. 30.11	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)

ईई. सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :—

1.	5 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा	रु. 4.22	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिन्दु)
2.	10 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा	रु. 4.80	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिन्दु)
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000	रु. 7.32	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिन्दु)

नोट :— अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी.

अगरबत्ती नियोजन में उपरोक्तानुसार मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु वर्तमान में शासन द्वारा 45 अधिसूचित नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन वर्गवार/जोनवार प्रभावशील होगी.

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम-2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (व्ही.डी.ए.) जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 में औसत अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा. जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी. इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा. उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में घोषित किया जावेगा.

अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है.

2. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक सम्मिलित होगा।

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 10-4/2016/16.—राज्य शासन एतद्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबंधों के अनुसरण में अधिनियम की अधिसूचित अनुसूची के भाग-1 की प्रविष्टि क्रमांक 2 में उल्लेखित “किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन” में पुनरीक्षण का प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-10-4/2016/16, दिनांक 02-02-2018 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 09-03-2018 में प्रकाशित किया था, जिसके संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 तथा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार पध्द के परामर्श अनुरूप “किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन” के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4191 (2001=100) के आधार पर जुलाई 2016 से जून 2017 तक अवधि में हुई औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक योग 6321 (4191+2130=6321 पाईट) के आधार पर नियत मूल वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को विलय करने के उपरान्त प्राप्त न्यूनतम वेतन की दरों में उक्त प्राप्त न्यूनतम वेतन में 20% की वृद्धि करते हुए एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के वर्गों के लिये, कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कालम (4) में दर्शाये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें पुनरीक्षित करता है तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार पुनरीक्षित की गई न्यूनतम वेतन की दरें इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी :—

अनुसूची

किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु. 96.24 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 539.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 539.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा.	निर्धारित न्यूनतम की दरों के अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल सूचकांक 6321 (1960=100) के ऊपर की देय होगी. परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना प्रतिवर्ष विगत जुलाई से जून के वर्ष के औसत सूचकांक जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा की जावेगी, के आधार पर देय होगा. परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर 1000 बीड़ी बनाने पर प्रति औसत बिन्दु एक पैसा रहेगी, जो आगामी अक्टूबर 2018 से श्रमिकों को देय होगी.
2.	रेलाई श्रमिक		
अ.	बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना		
1.	लेबल चिपकाने तथा पुड़े को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य.	रु. 53.18 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है.	रु. 56.35 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार
ब. झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रु. 48.06 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार
2.	झिल्ली लगाना	रु. 35.20 प्रति 1000 कट्टों पर	1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार
3.	लेबल लगाना	रु. 13.10 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु. 13.44 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार
स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो.	रु. 198.88 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो.	रु. 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो.	रु. 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर

नोट :— बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छांटने या जांच करने वाले, तंबाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राइवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन, कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे.

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा.

1.	उच्च कुशल	—	ड्राइवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउंटेंट, डाटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर आपरेटर), मुनीम, कैशियर, हेड क्लर्क.
2.	कुशल	—	स्टोर कीपर, ड्राइवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, गोडाउन कीपर, क्लर्क, बिलमेन.
3.	अर्ध कुशल	—	बीड़ी छांटने या जांच करने वाले, भट्टी वाला.
4.	अकुशल	—	ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक.

बीड़ी नियोजन में उपरोक्तानुसार मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु वर्तमान में शासन द्वारा 45 अधिसूचित नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन वर्गवार/जोनवार प्रभावशील होगी.

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है.

2. परिवर्तनशील महंगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (1960=100) पर आधारित है. 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जुलाई से जून तक जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक-3 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तंभ 4 में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी. 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की वृद्धि की गणना मत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी.
3. निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा.
4. जहाँ नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाकू तेन्दूपत्ता, धागा, पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा.
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा.
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, यह भी सम्मिलित होगा.
7. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि यह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो यह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, विशेष सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 10-15/2018/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा यह घोषित करती है कि कारखानों में महिला कामगारों को शाम 07.00 बजे से 10.00 बजे के मध्य, कतिपय शर्तों, जो कि महिला कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु विहित किया जाये, के साथ नियोजित किया जा सकेगा, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाना के मालिक के आवेदन पर कारखाना का मुख्य निरीक्षक, महिला कामगारों से सम्यक् परामर्श और सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, उपरोक्त उल्लिखित शर्तों सहित कारखाना में महिला कामगारों के नियोजन हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप-सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 10-15/2018/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2018/16, दिनांक 25-09-18 का अंग्रेजी अनुसार राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप-सचिव.

Atal Nagar, Raipur the 25th September 2018

No. F-10-15/2018/16.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby, declares that women workers may be employed in the factories between 7 P.M. and 10 P.M. with certain conditions as may be prescribed to ensure health, safety and welfare of the women workers. on application from occupier of any factory, registered under the said Act, the Chief Inspector of the Factory, may after due consultation and obtaining the consent of women workers, grant permission for employment of women workers in the factory with the above mentioned conditions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DIVYA UMESH MISHRA, Deputy Secretary.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक/6044/एफ-02/02/PMFBY/2018/14-2.— भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13017/01/2016-Credit-II (Pt. I) Elec. 60432) दिनांक 03-08-2018 के अनुक्रम में एतद्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2018 में क्लस्टर क्र.-4 (जिला जशपुर, बलरामपुर, बीजापुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम) के लिए प्रीमियम कटौती की तिथि को संलग्न पत्रानुसार अधिसूचित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 7-60/2014/32.—इस विभाग की सूचना क्रमांक 1504/2382/32/2007, दिनांक 24-07-2008 द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत नया रायपुर विकास योजना 2031 अंगीकृत की गई है तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 1-131/2008/32, दिनांक 28-08-2018 द्वारा “नया रायपुर” का नाम “अटल नगर” किया गया है। अतः उक्त तिथि 28-08-2018 से “नया रायपुर विकास योजना 2031” के स्थान पर “अटल नगर विकास योजना 2031” के नाम से जानी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 10 अक्टूबर 2018

क्रमांक 468/09/भू.अ./अ.वि.अ./अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	भरचट्टी प.ह.नं. 07	0.867	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेरला (छ.ग.).	सोढ़ - रेवे - देवरबीजा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेरला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

क्रमांक 462/भू.अ./अ.वि.अ./अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-बेरला
(ग) नगर/ग्राम-देवरबीजा, प.ह.नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.354 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1076/2	0.038
1079/2	0.002
1126	0.008

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
1129	0.004		
1153	0.012		
1155/1	0.017	377	0.011
1155/2	0.008	380/1	0.024
1156	0.012	380/2	0.024
1161	0.040	382	0.021
1159	0.017	803	0.022
1166/2	0.021	79	0.01
1166/3	0.021	72/3	0.003
1160	0.018	76/1	0.014
1080/2	0.018	76/3	0.006
1086	0.006	75/3	0.002
1117/2	0.008	75/4	0.002
1118/2	0.004	75/8	0.003
1123	0.002	75/2	0.008
1124	0.009	74/2	0.013
1111/1	0.042	60	0.014
1163/2	0.047	57	0.014
योग	0.3534	76/2	0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोढ़ रेवे देवरबीजा मार्ग निर्माण.		56/2	0.02
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.		101	0.008
		102/1	0.007
		102/2	0.007
बेमेतरा, दिनांक 11 अक्टूबर 2018		102/3	0.007
		99	0.007
क्रमांक 466/भू.अ./अ.वि.अ./अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		98/1	0.005
		92/2	0.004
		95/2	0.012
		91	0.025
		796/1	0.006
		176	0.007
अनुसूची		योग	0.310
(1) भूमि का वर्णन-		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोढ़ रेवे देवरबीजा मार्ग निर्माण.	
(क) जिला-बेमेतरा		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
(ख) तहसील-बेरला			
(ग) नगर/ग्राम-सिंघौरी, प.ह.नं. 10			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.310 हेक्टेयर			

बेमेतरा, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

क्रमांक 470/भू.अ./अ.वि.अ./अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-बेरला
(ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प.ह.नं. 03
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.0592 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
384/2	0.004
384/1	0.001
384/4	0.005
385	
391	
392	0.005
394	0.007
399	
810	0.001
410	0.002
115/6	
406	0.003
48/1	0.01
53	0.02
योग	0.0592

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सोढ़ रेवे देवरबीजा मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

क्रमांक 472/भू.अ./अ.वि.अ./अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-बेरला
(ग) नगर/ग्राम-सोढ़, प.ह.नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.6142 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
498/2	0.008
498/4	0.009
500	0.048
504	0.017
506	0.019
508/1	0.041
508/3	0.025
508/2	0.023
509/1	0.015
509/2	0.018
566	0.040
542	0.021
497	0.002
544	0.009
548	0.021
547/2	0.014
551	0.017
552	0.01
554	0.021
555	0.028
558/1	0.021
558/2	0.001
559	0.016
561	0.014
560	0.009

(1)	(2)	(1)	(2)
563/1	0.003	81	0.02
564	0.054	80	0.048
714	0.004	78/2	0.02
719/1	0.018	78/5	0.007
719/3	0.013	78/1	0.004
710/4	0.018	77/3	0.015
719/2	0.018	338	0.029
553	0.01	339	0.02
543	0.01	359/2	0.04
		359/3	0.01
योग	0.6142	359/1	0.01
		356	0.011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोढ़ रेवे		365	0.01
देवरबीजा मार्ग निर्माण.		364/3	0.01
		355/2	0.04
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		354	0.017
(राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.		24/4	0.01
		योग	0.3823

बेमेतरा, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

क्रमांक 474/भू.अ./अ.वि.अ./अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-सिरसा, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.382 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77/2	0.019
83	0.018
82	0.02
78/4	0.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोढ़ रेवे देवरबीजा मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

क्रमांक 476/भू.अ./अ.वि.अ./अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-रेवे, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.0874 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	बेमेतरा, दिनांक 15 अक्टूबर 2018																		
(1)	(2)	क्रमांक 464/भू.अ./अ.वि.अ./अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—																		
397/1	0.004	<div>अनुसूची</div> <div>(1) भूमि का वर्णन— (क) जिला-बेमेतरा (ख) तहसील-बेरला (ग) नगर/ग्राम-लेंजवारा, प.ह.नं. 16 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर</div> <table><tr><th>खसरा नम्बर</th><th>रकबा (हेक्टेयर में)</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>914</td><td>0.015</td></tr><tr><td>914</td><td>0.001</td></tr><tr><td>862/1</td><td>0.004</td></tr><tr><td>854</td><td>0.019</td></tr><tr><td>854</td><td>0.004</td></tr><tr><td>514</td><td>0.027</td></tr><tr><td>योग</td><td>0.070</td></tr></table>	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	914	0.015	914	0.001	862/1	0.004	854	0.019	854	0.004	514	0.027	योग	0.070
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)																			
(1)	(2)																			
914	0.015																			
914	0.001																			
862/1	0.004																			
854	0.019																			
854	0.004																			
514	0.027																			
योग	0.070																			
397/2	0.003																			
398	0.003																			
399	0.002																			
407	0.002																			
501	0.002																			
502/4	0.002																			
502/5	0.001																			
508/1	0.002																			
508/2	0.001																			
590	0.004																			
591	0.003																			
593/1	0.001																			
593/2	0.001																			
669/1	0.002																			
691/1	0.011																			
765	0.004																			
769	0.009																			
771	0.002																			
772	0.002																			
774	0.002																			
775	0.002																			
780/1	0.001																			
780/2	0.004																			
781	0.002																			
782	0.001																			
783	0.002																			
784	0.001																			
785	0.003																			
786	0.001																			
789	0.002																			
795	0.005																			
795	0.001																			
795	0.002																			
795	0.002																			
योग	0.0874																			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोढ़ रेवे देवरबीजा मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2018

क्रमांक क/भू-अर्जन अधि./रीडर-1/2018/1568.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्डुरोड
(ग) नगर/ग्राम-सारबहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

(1)

रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

16/1

0.040

योग

1

0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सालकारोड-अनुपपुर रेल दोहरीकरण परियोजना के अन्तर्गत, सारबहरा-पेण्डुरोड के मध्य रेल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डुरोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्रमांक/1049/रा.प्र.क्र. 07 ब/121 वर्ष 2017-18.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के तहत के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक नवीन राजस्व ग्राम होगा, अर्थात :—

क्र.	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हे. में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की सीमाएं	पटवारी हल्का नं.	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	नगपुरा	279.200 हे.	उत्तर में :— ग्राम गातापार दक्षिण में :— ग्राम दतान पूर्व में :— ग्राम दतान पश्चिम में :— ग्राम बेल्ला एवं ग्राम परसाडीह.	23	दतान	पलारी	बलौदाबाजार-भाटापारा

No./1049/Rcn No. 07 B/121 Year 2017-18.—Whereas, Section 90 Read with Section 73 of C.G. Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), The Powers of Settlement Officers Relating to Constitution of Revenue Villages have been vested.

Therefore, in Exercise of the Powers Conferred By Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), It is, hereby Declare That Village Shown in Column (2) of Schedule Below Shall be one New Revenue Village from the date of This Notification, Namely :—

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In Hectare)	Boundaries of Village	P.H.N.	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nagapura	279.200 Hect.	North :— Village Gatapar South :— Village Datan East :— Village Datan West :— Village Belha & Village Parsadheeh	23	Datan	Palari	Balodabazar-Bhatapara

बलौदाबाजार, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्रमांक/1051/रा.प्र.क्र. 69 ब/121 वर्ष 2017-18.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के तहत के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक नवीन राजस्व ग्राम होगा, अर्थात :—

क्र.	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हे. में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की सीमाएं	पटवारी हल्का नं.	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बम्हनमुड़ी	353.862 हे.	उत्तर में :— ग्राम छुईया दक्षिण में :— ग्राम पनगांव पूर्व में :— ग्राम बिटकुली पश्चिम में :— ग्राम परसाभदेर एवं ग्राम हलवाई खपरी.	20	पनगांव	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार-भाटापारा

No./1051/Rcn No. 07 B/121 Year 2017-18.—Whereas, Section 90 Read with Section 73 of C.G. Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959). The Powers of Settlement Officers Relating to Constitution of Revenue Villages have been vested.

Therefore, in Exercise of the Powers Conferred By Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), It is, hereby Declare That Village Shown in Column (2) of Schedule Below Shall be one New Revenue Village from the date of This Notification, Namely :—

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (In Hectare)	Boundaries of Village	P.H.N.	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bamhanmudi	353.862 Hect.	North :— Village Chhuiya South :— Village Pangaon East :— Village Bitkuli West :— Village Parsabhader & Village Halwai Khapari	20	Pangaon	Baloda-bazar	Balodabazar-Bhatapara

जे. पी. पाठक,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th September 2018

No. 1071/Confdl./2018/II-2-1/2018.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additonal Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No.	Name & presently posted as	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Ashish Pathak, III Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Gharghora	Raigarh	Additional District & Sessions Judge.

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2018

क्रमांक 10481/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद् द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, डोण्डीलोहारा अपने घोषित कार्य स्थल डोण्डीलोहारा के अतिरिक्त दल्लीराजहरा में भी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में (उन दिनों को छोड़कर जिनमें उन्हें किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्षता करना है) बैठक करेंगे।

No. 10481/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-II/JMFC, Dondilohara in addition to his place of sitting at Dondilohara declared shall also sit at Dallirajhara in every month for first & third week (except the days in which She/he is supposed to preside over the juvenile justice Board).

Bilaspur, the 2nd November 2018

No. 1181/Confdl./2018/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Shruti Shukla, Member of Lower Judicial Service, presently posted as II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Bilaspur, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Shruti Dubey” in place of “Ku. Shruti Shukla” and to incorporate the name of her husband Shri Gopal Krishna Dubey in her service records, It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 2nd November 2018

No. 1183/Confdl./2018/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Barkha Rani Kasar, Member of Lower Judicial Service, presently posted as VII Civil Judge Class-II, Durg, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Barkha Rani Verma” in place of “Ku. Barkha Rani Kasar” and to incorporate the name of her husband Shri Ashish Verma in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 2nd November 2018

No. 1185/Confdl./2018/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Savita Singh, Member of Lower Judicial Service, presently posted as II Civil Judge Class-II, Balod, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Savita Singh Thakur” in place of “Ku. Savita Singh” and to incorporate the name of her husband Shri Santosh Thakur in her service records, It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By the order of Hon'ble the Chief Justice,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

Bilaspur, the 29th October 2018

No. 84/L.G./2018/II-3-26/2014.—Shri Sirajuddin Qureshi, Judge, Family court, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 04 days from 17-09-2018 to 20-09-2018 along with permission to remain out of headquarters from the night of 14-09-2018 till the morning of 22-09-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that is Shri qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 167 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th October 2018

No. 85/L.G./2018/II-3-23/2010.—Shri Shailesh Kumakr Tiwari, Judge, Family court, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 03 days from 01-01-2018 to 03-10-2018 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 29-09-2018 till 03.10.2018 and earned leave for 03 days from 15-10-2018 to 17-10-2018 along with permission to remain out of headquarters after the court hours of 12-10-2018 till before the court hours of 22-10-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 296 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th October 2018

No. 86/L.G./2018/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivatava, District & Sessions Judge Jashpur is hereby, granted earned leave for 03 days from 15-10-2018 to 17-10-2018 along with permission to leave headquarters from the evening 06.00 p.m. to 12-10-2018 till the morning 10.00 a.m. of 22-10-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 266 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th October 2018

No. 87/L.G./2018/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Principal judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-09-2018 to 14-09-2018 along with permission to remain out of headquarters after the work of National Lok Adalat on 08-09-2018 till 14-09-2018 and earned leave for 01 days on 01-10-2018 along with permission to remain out of headquarters from 30-09-2018 to 02-10-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 300+04 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th October 2018

No. 88/L.G./2018/II-3-65/2001.—Shri Jagdamba Rai, District & Session Judge, Dhamtari is hereby, granted commuted leave for 10 days from 19-09-2018 to 28-09-2018.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rai, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 437 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th October 2018

No. 89/L.G./2018/II-3-43/2007.—Shri Rajendra Pradhan, Judge Family Court, Jagdalpur is hereby, granted commuted leave for 14 days from 08-08-2018 to 21-08-2018.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

certified that if Shri Pradhan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 412 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 29th October 2018

No. 90/L.G./2018/II-2-38/2018.—Shri Sahabuddin Qureshi, Officer-on-Special Duty-cum-Central Project co-ordinator, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 17-09-2018 to 20-09-2018 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 14-09-2018 till the morning of 22-09-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave 163 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By Order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (Admn.).
